SHRI KHURSHED ALAM KHAN: After the ban was imposde, there have been no export of monkeys of any sort.

श्री चतुर्भुज: यहां पर बन्दरों के स्मगलिंग या निर्यात की बात कही गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उनकी उपयोगिता के बारे में सोचा है । है ।

श्री खुर्शीद आलम खान : हमने न निर्यात का सोचा है, न स्मगलिंग का सोचा है । जो स्मगल करते हैं, वे जानें ।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: He has not given the reason. I do not know why the Russians have special love and affection for Indian monkeys. However, I would like to ask one question with reference to the ban. And the question is: whether it is not a fact that the immediate reason to ban the export of monkeys was that the monkeys exported to the United States were being secretly used by the American defence authorities to stave off the effect of radiation of atom bombs; and if so, whether a condition has been imposed in the trade agreement between 1981 and 1985, with the Russians. If not, why not and why is there a special treatment for the Russians?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: My colleague has already explained that it is a banned item. And, therefore, we explained our position that we are not in a position to export monkeys to USSR. As to the question why they are taking place, it is known to the hon. Member that mainly, these are taken for medical experiments--and sometimes to serve zoological interests—but mainly for medical experiments.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Can the US utilise these monkeys for these purposes? That is the main point.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: When I have put a ban on exports, there is no question of discussion all these things. I am not exporting at all.

Improvement in Civil Aviation during Sixth plan period

+

*564. SHRI RAJESH KUMAR SINGH:

SHRI ASHOK GEHLOT:

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether any plan outlay has been provided by Government to improve the Civil Aviation in the country during the Sixth Plan period;

(b) if so, the names of new cities which are likely to be brought on the air map of India during the Sixth Plan; and

(c) funds allocated for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISRTY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) Yes, Sir.

(b) Following new places have recently been brought on the air map. Kamalpur, Kailashahar, Rupsi, Barapani, Tezu and the following are proposed to be brought on the air map. passighat, Along, Zero, Daparijo; Cooch-Behar, Itanagar, Aizwal, Sadiya and Gangtok. Apart from these, a new aerodrome is likely to be developed in Calicut in Kerala State.

(c) Rs. 153.50 crores.

श्री राजेश कुमार सिंह: मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में उन स्थानों की सूची दी है, जिन्हें भारत के विमान-सेवा मानचित्र में शामिल किये जाने, या जहां पर एयरपोर्ट बनाने, की योजना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उन स्थानों को वरीयता देने का आधार तथा मापदंड क्या है: क्या यह कनसिडर किया गया है कि वहां टूरिस्ट्स का आना-जाना ज्यादा था, या वहां आवागमन की दिक्कतें थी, या उनके बारे में राजनैतिक दबाव था, या

किसी प्रभावशाली व्यक्ति की वजह से ऐसा किया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन जगहों पर देश-विदेश से ज्यादा टूरिस्ट्स जाते हैं, क्या उनके बारे में भी विशेष रूप से विचार किया गया है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): इस तरह की जगहों पर विचार करने के दो कारण हैं। एक तो वहां हवाई जहाज से आने-जाने वालों का पोटेन्शियल कितना है, कितने लोग आ-जा सकते हैं, और दूसरा कारण इंडियन एयरलाइन्स एसेस करके बताती है, उसके आधार पर हम उसको डेवलप करते हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह: क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि आगरा एक टूरिस्ट केन्द्र है और वहां विदेशों से भी काफी लोग आते हैं, वहां आर्मी का एयरपोर्ट है, डिफेन्स विभाग के पास है इसलिये वहां ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह का प्रस्ताव किया था, सुझाव सरकार के पास भेजा था। मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह का सुझाव उनके पास आया था तो उसमें क्या उल्लेख है?

दूसरी बात यह है कि पहले भी उसके सर्वे की चर्चा आई थी। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म विभाग ने उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को आग्रह किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस पर कोई विचार हो रहा है या आगे किया जायेगा? आगरा एक महत्वपूर्ण स्थान है, दुनिया का सबसे बड़ा एतिहासिक ताजमहल वहां पर है और उसे देखने के लिये दुनिया के लोग वहां पर आते हैं, लेकिन वहां पर लोगों को सही मायनों में पहुंचने की पूरी सुविधाएं नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप चार्टर्ड प्लेन को वहां जाने की अनुमति प्रदान करेंगे क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक जाम रहता है? क्या आप इस बारे में विचार करेंगे कि ऐसी सुविधा चार्टर्ड प्लेन को मिल सके जिससे वह लैंडिंग वहां पर कर सके?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा: केवल आगरा ही एक ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां कि हमारे इंडियन एयरलाइन्स के हवाई जहाज उतरते हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई एयरोड्रोम्स ऐसे हैं जो डिफेन्स विभाग के कंट्रोल में हैं। जहां तक आगरे में पैसेन्जर्स के लिए सुविधा का सवाल है, कुछ सुविधाएं तो हमने बढ़ाई हैं और आगरा जाने में इस वक्त हमें कोई कठिनाई नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि जो ट्रैफिक आगरे का है उस को हम इन्डियन एयरलाइन्स से मौजूदा एयरपोर्ट के जरिये ही मीट कर सकते हैं।

श्री अशोक गहलोत: अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि कुछ क्राइटोरिया हैं जिनके अन्तर्गत नये शहरों को इन्कलूड किया है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस क्राइटीरिया के अन्तर्गत राजस्थान के कोटा और जैसलमेर जैसे शहर भी आते हैं या नहीं जिससे वहां एयरोड्रम दिये जा सकें। इसके अलावा जोधपुर राजस्थान का एक मशहूर शहर है, उसमें लम्बे अर्से से एयर सर्विस चल रही थी, जनता सरकार के जमाने में उसे बन्द कर दिया गया था। अभी मंत्री महोदय ने 4 महीने पहले ही उसे पुनः शुरू किया है। जब हमने उनसे मुलाकात की थी तो उन्होंने वायदा किया था कि जल्दी ही इसको रैगुलर वर दंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह कब तक इसको रैगुलर करने जा रहे हैं?

1976 में इस विभाग के मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जोधपुर शहर को जल्दी ही बोइंग सर्विस से जोड़ दंगे, उसके बाद सर्विस बन्द हो गई थी, अब आपने पुनः शुरू की है, तो क्या आप इसे बोइंग सर्विस से भी जोड़ने जा रहे हैं?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा: जोधपुर के महत्व और वहां के ट्रैफिक के महत्व को देखते हुए हमने हाल ही में एयरलाइन्स को

सर्विस वहां इन्ट्रोड्यूस की है । वहां इसकी फ्रीक्वेन्सी और बढ़ सकती है या नहीं, जैसा मैंने अपने भाषण में भी बताया था कि यह डिपेन्ड करता है कि वहां कितने लोग जाने-आने वाले हैं । अभी हम उसको स्टडी कर के देख रहे हैं और अगर लोड फैक्टर जस्टीफाई करेगा कि हमारी फ्रिक्वेन्सी वहां बढ़नी चाहिये तो हम उस पर विचार करेंगे। जहां तक बोइंग सर्विस देने का सवाल है माननीय सदस्य को मालूम होगा कि हर एयरपोर्ट पर बोइंग सर्विस नहीं दे सकते हैं, जब तक कि वह एयरपोर्ट बोइंग सर्विस के लायक न हो और इसके लिये हमारे पास बोइंग एयरक्राफ्ट भी होने चाहियें । मैं देखूंगा, अगर जोधपुर का एयरपोर्ट बोइंग के लायक है तो इस पर विचार करेंगे लेकिन यह इस पर भी डिपेन्ड करता है कि हमारे पास बोइंग कितने हैं ?

SHRI K. OBUL REDDY: May I know from the hon Minister the criterion on which the cities are brought on the air map of the country? Is the Government aware that Cuddapah City with a population of 1,20,000 people is developing fast and is centrally situated between Madras, Bangalore and Hyderabad. There is already an aerodrome established some 20 years back. May I know whether Cuddapah City will be brought on the air map?

SHRI A. P. SHARMA: There is no such proposal.

गुजरात में हथकरघा उद्योग का विकास

*565. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गुजरात में हथ-करघा उद्योग के विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है अथवा बनाए जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गुजरात के हथकरघा उद्योग के विकास पर अनुमानत कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) ये योजनाएं कब और किन स्थानों पर शुरू की जायेंगी और उनका ब्यौरा क्या है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHED ALAM KHAN): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The handloom industry in Gujarat is being helped under the various centrally sponsored schemes in the handloom sector. Besides, the Government of Gujarat have their own schemes under the State plan.

(b) The list of schemes and the financial assistance given from the Centre for the centrally sponsored schemes are given in the Annexure.

According to information furnished by Government of Gujarat a special package scheme for handloom cooperatives is being implemented. This includes financial assistance to handloom weavers cooperatives, share capital loan, managerial subsidy, modern tools and equipments, workshed godowns, dyeing facilities working capital through banks, reserve fund subsidy, stipend to trainees, education tour to weavers etc. The intensive development project is meant for the development of the looms outside the cooperative sector and it has covered in all 3500 looms upto March 1981.

There is also a scheme for setting up a separate institute of handloom technology in Gujarat for providing higher certificate course in handloom weaving and printing. Extimated expenditure during 1980-81 for all the schemes is expected to be Rs. 63.50 lakhs. The number of persons likely to be benefited out of all these schemes will be 10,000 weavers under the package scheme, 3500 under intensive development schemes and 40 wea-